



## उदारीकरण पूर्व चरण के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह(एफडीआई) का विकास और

### रुझान

निर्मला देवी, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर

डॉ रतनेश चंद्रा, शोध पर्यवेक्षक, अर्थशास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर

### सार

एफडीआई भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मौद्रिक स्रोत है। 1991 के संकट के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और तब से देश में एफडीआई में लगातार वृद्धि हुई है। भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पर शीर्ष 100-क्लब का हिस्सा है और ग्रीनफील्ड एफडीआई रैंकिंग में विश्व स्तर पर नंबर 1 पर है। इस अध्ययन में उदारीकरण पूर्व चरण के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह (एफडीआई) का विकास और रुझान के बारे में चर्चा की है।

**मुख्य शब्द:** उदारीकरण पूर्व चरण, विदेशी निवेश अंतर्वाह, विकास, रुझान

### परिचय

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) कोई नई घटना नहीं है। इसकी नींव 1500 ईस्वी में देखी जा सकती है जब पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी पहली कपड़ा इकाई शुरू की , उसके बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों के रूप में भारत में प्रवेश किया , बाद में उद्योगपति बन गए और उनमें से कुछ शासक बन गए। इन व्यापारियों के बीच 1800 ई. तक घोर प्रतिस्पर्धा थी और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली और उसने भारत का उपनिवेश बना लिया। वाणिज्यिक पैमाने पर भारत में एफडीआई का प्रवेश 1875 में खनन, चाय बागान, रेलवे, बीमा, बिजली के उत्पादन और वितरण , थोक और खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रारंभिक निवेश के साथ शुरू हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय , एफडीआई का महत्वपूर्ण भंडार



था जो यूनाइटेड किंगडम से था। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने राज्य हस्तक्षेप नीति के साथ औद्योगीकरण की रणनीति अपनाई। घरेलू उद्यमों द्वारा निवेश में वृद्धि हुई जिसने एफडीआई के पैटर्न को प्रभावित किया।

भारत सरकार ने एफडीआई के प्रति उदार नीति अपनाई क्योंकि इसे आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक माना जाता था। यह औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन था जो लाइसेंसिंग समझौतों और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के माध्यम से अनुपलब्ध था। **1991** से पहले, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशके प्रति

सरकार का रवैया धीरे-धीरे उदार था। प्रौद्योगिकी आयात में, वित्तीय और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी गई। यहां तक कि प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौतों के लिए भी तकनीकी शुल्क और रॉयल्टी भुगतान की दरों पर प्रतिबंध थे। दूसरी ओर, नामित उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी, घरेलू भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने, निर्यात दायित्वों, स्थानीय सामग्री खंड, स्थानीय

आर एंड डी को बढ़ावा देने, और इसी तरह की अलग-अलग शर्तों के अधीन। एफडीआई के प्रति सरकार द्वारा प्रतिबंधित नीति के उदाहरण को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम **(1974)** के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जो निर्दिष्ट करता है कि विदेशी फर्मों की इक्विटी में केवल **40** प्रतिशत तक

की हिस्सेदारी है, छूट सरकार के विवेक पर थी। शाखा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति नहीं थी; विदेशी सहायक कंपनियों को घरेलू पूंजी बाजार में अपनी इक्विटी होल्डिंग को धीरे-धीरे **40** प्रतिशत से कम करने के लिए प्रेरित किया गया। विदेशी ब्रांडों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था और हाइब्रिड घरेलू ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उदाहरण के लिए हीरो-होंडा। माना जाता है कि इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक नीति में घरेलू तकनीकी क्षमता मंद होती है (जैसा कि भारतीय सामानों की खराब गुणवत्ता में परिलक्षित होता है), जिससे श्रम-प्रधान निर्माताओं के निर्यात अवसर का नुकसान होता है।

हालांकि, कहा जाता है कि इस प्रकार की नीति ने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार शुरू करने और निर्यात बाजारों की तलाश करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी पर घरेलू भागीदारों द्वारा 'किराया मांगने' को प्रोत्साहित किया है (अहलूवालिया, **1985**)। **1980** के दशक में, विदेशी निवेश नियमों में धीरे-धीरे ढील दी गई। यह **1982** में जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम छोटी कार

द्वारा प्रतिबंधित नीति के उदाहरण को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम **(1974)** के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जो निर्दिष्ट करता है कि विदेशी फर्मों की इक्विटी में केवल **40** प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है, छूट सरकार के विवेक पर थी। शाखा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति नहीं थी; विदेशी सहायक कंपनियों को घरेलू पूंजी बाजार में अपनी इक्विटी होल्डिंग को धीरे-धीरे **40** प्रतिशत से कम करने के लिए प्रेरित किया गया। विदेशी ब्रांडों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था और हाइब्रिड घरेलू ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उदाहरण के लिए हीरो-होंडा। माना जाता है कि इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक नीति में घरेलू तकनीकी क्षमता मंद होती है (जैसा कि भारतीय सामानों की खराब गुणवत्ता में परिलक्षित होता है), जिससे श्रम-प्रधान निर्माताओं के निर्यात अवसर का नुकसान होता है।

हालांकि, कहा जाता है कि इस प्रकार की नीति ने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार शुरू करने और निर्यात बाजारों की तलाश करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी पर घरेलू भागीदारों द्वारा 'किराया मांगने' को प्रोत्साहित किया है (अहलूवालिया, **1985**)। **1980** के दशक में, विदेशी निवेश नियमों में धीरे-धीरे ढील दी गई। यह **1982** में जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम छोटी कार

द्वारा प्रतिबंधित नीति के उदाहरण को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम **(1974)** के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जो निर्दिष्ट करता है कि विदेशी फर्मों की इक्विटी में केवल **40** प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है, छूट सरकार के विवेक पर थी। शाखा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति नहीं थी; विदेशी सहायक कंपनियों को घरेलू पूंजी बाजार में अपनी इक्विटी होल्डिंग को धीरे-धीरे **40** प्रतिशत से कम करने के लिए प्रेरित किया गया। विदेशी ब्रांडों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था और हाइब्रिड घरेलू ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उदाहरण के लिए हीरो-होंडा। माना जाता है कि इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक नीति में घरेलू तकनीकी क्षमता मंद होती है (जैसा कि भारतीय सामानों की खराब गुणवत्ता में परिलक्षित होता है), जिससे श्रम-प्रधान निर्माताओं के निर्यात अवसर का नुकसान होता है।

हालांकि, कहा जाता है कि इस प्रकार की नीति ने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार शुरू करने और निर्यात बाजारों की तलाश करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी पर घरेलू भागीदारों द्वारा 'किराया मांगने' को प्रोत्साहित किया है (अहलूवालिया, **1985**)। **1980** के दशक में, विदेशी निवेश नियमों में धीरे-धीरे ढील दी गई। यह **1982** में जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम छोटी कार



परियोजना मारुति की स्थापना का प्रतीक था। पेप्सी के भारत में प्रवेश करने के बाद। नई औद्योगिक नीति (एनईपी) 1991 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। अब विदेशी निवेश को दुर्लभ पूंजी, प्रबंधकीय कौशल और प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में माना जाता था जिसे एक खुले प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण में आवश्यक माना जाता था। दशक के दौरान, भारत ने न केवल अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी, बल्कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की भी अनुमति दी। इसके अलावा, विदेशी फर्मों को घरेलू कंपनियों के समान वातावरण प्रदान करने के लिए कानूनों को सरल बनाया गया।

### साहित्य की समीक्षा

राव और सिंह (2017)के अध्ययन में कहा गया है कि "प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकी क्षेत्रीय एकाग्रता चिंता का विषय नहीं है यदि श्रमिक गतिशीलता यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि श्रमिक वहां जा सकते हैं जहां नई नौकरियां पैदा होती हैं। " हालांकि, शीर्ष-स्तर बताते हैं कि भारतीय श्रम गतिशीलता अपेक्षाकृत कम है, "ग्रामीणों में आबादी का 0.5 प्रतिशत से कम और शहरी क्षेत्रों में 4 प्रतिशत आबादी आर्थिक विचार (या रोजगार) के कारणों से चली गई।

प्रदीप बैज (2017) "एफडीआई इनफ्लो रोड टू इंडियाज रैपिड डेवलपमेंट " शीर्षक वाले शोध पत्र में बाजार सर्वेक्षण और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्ज किए गए, जो कि 70 प्रतिशत विदेशी सर्वेक्षण किए गए निवेशक अपने भारतीय परिचालन से लाभ कमा रहे थे। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विनिर्माण विदेशी निवेशक ज्यादातर देश की बुनियादी ढांचे की स्थिति से असंतुष्ट थे, 42 प्रतिशत ने भागों और बिजली सुविधाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया, और 54 प्रतिशत कंपनियों ने सड़कों और राजमार्गों की स्थिति का मूल्यांकन किया।



## अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है , जिसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया गया है जैसे कि औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार के समाचार पत्र ; भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका ; व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) और विश्व बैंक द्वारा विभिन्न विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर)।

## डेटा विश्लेषण और व्याख्या

स्वतंत्रता के समय , अंग्रेजों द्वारा निभाई गई पिछली शोषणकारी भूमिका के कारण विदेशी पूंजी के प्रति सरकार का रवैया अविश्वासों में से एक था। सरकार ने एफडीआई को आकार देने और नियंत्रित करने के लिए कानूनी और नीतिगत प्रावधानों की व्याख्या करने के साथ -साथ लागू करने में पूर्ण विवेक और अधिकार का प्रयोग किया। इस खंड में , उदारीकरण पूर्व चरण में भारत में एफडीआई प्रवाह की वृद्धि और प्रवृत्तियों का पता लगाया जाएगा। उदारीकरण-पूर्व चरण के दौरान एफडीआई अंतर्वाह का समग्र रुझान। स्वतंत्रता के बाद, सतर्क एफडीआई नीति के परिणामस्वरूप भारत में एफडीआई प्रवाह का निम्न स्तर हुआ। **1948** से **1980** तक भारत में आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समग्र वृद्धि और प्रवृत्ति को तालिका 1 और **1981** से **1990** तक तालिका 2 में दिखाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 'अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति और देनदारियों' पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि **1948** में भारत में एफडीआई **256** करोड़ रुपये था। यह बढ़कर रुपये हो गया। मार्च **1980** में **933.2** करोड़ (तालिका 1)। प्राकृतिक संसाधन चाहने वाले और व्यापारिक प्रकार के एफडीआई स्टॉक उस समय थोक में थे।



**तालिका 1: 1948 से 1980 तक भारत में एफडीआई अंतर्वाह स्टॉक(करोड़ रुपये में)**

वर्ष	एफडीआई अंतर्वाह
मध्य 1948	256.0
मार्च 1964	565.5
मार्च 1974	916.0
मार्च 1980	933.2
स्रोत: कुमार 1995	

तालिका 2 से यह भी स्पष्ट है कि 1981 में एफडीआई अंतर्वाह की राशि \$92 मिलियन थी, 1989 में यह 252 मिलियन डॉलर के अपने चरम पर पहुंच गई , उसके बाद 1990 में यह घटकर 237 मिलियन डॉलर हो गई। समय अवधि के दौरान समग्र एफडीआई अंतर्वाह में उतार -चढ़ाव थे। 1981 से 1990 के बीच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में 2.6 गुना वृद्धि हुई है। यह 19.1 प्रतिशत के सीएजीआर (वास्तविक एफडीआई प्रवाह) के साथ बढ़ा।

**तालिका 2: 1981 से 1990 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि और रुझान  
(अमेरिकी डॉलर मिलियन)**

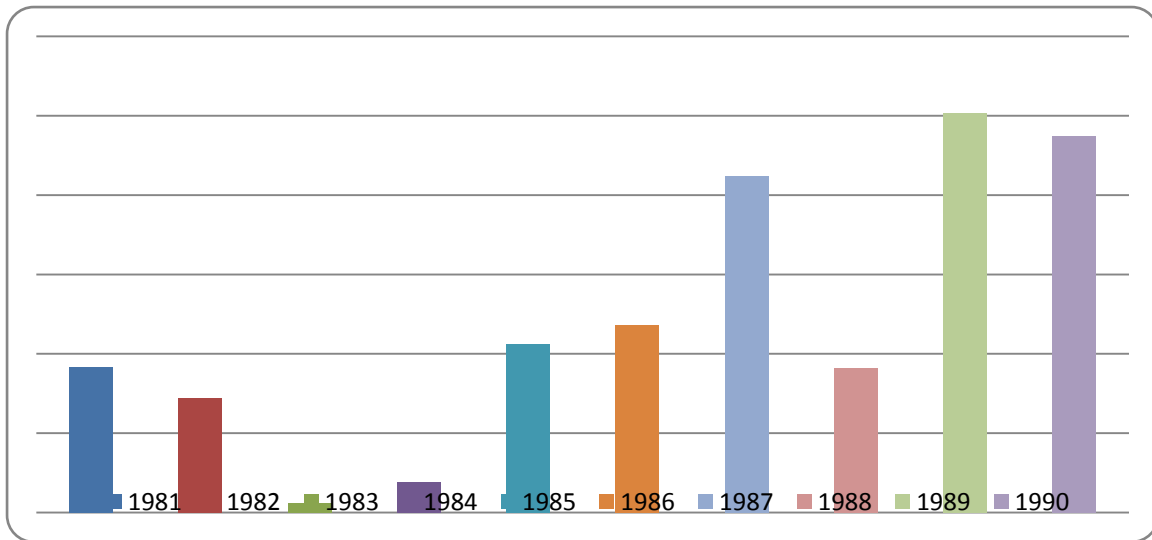
वर्ष	वास्तविक आवक एफडीआई	पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर	वृद्धि सूचकांक आधार वर्ष 1981
1981	92	--	100
1982	72	-21.7	-21.7
1983	6	-91.7	-93.5
1984	19	216.7	-79.3
1985	106	457.9	15.2



1986	118	11.3	28.3
1987	212	79.7	130.4
1988	91	-57.1	-1.1
1989	252	176.9	173.9
1990	237	-5.9	157.6
सीएजीआर (%)	19.1		

स्रोत: जी अख्तर, आईजेएचएसएसआई (2013)

1981 से 1990 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह की समान प्रवृत्ति को भी चित्र 1 में दर्शाया गया है।



चित्र 1: 1981 से 1990 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रुझान

स्रोत: जी अख्तर, आईजेएचएसएसआई (2013)

उपरोक्त आंकड़े 1 से स्पष्ट है कि एफडीआई अंतर्वाहों में व्यापक उतार-चढ़ाव थे। यह 1983 में सबसे कम और 1989 में सबसे ज्यादा था। 1980 के दशक की अवधि अर्ध उदारीकरण का दौर था।



• उदारीकरण पूर्व चरण के दौरान देश-वार एफडीआई अंतर्वाह की प्रवृत्तियां

भारत में 1981 से 1990 तक देश-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह तालिका 3 में दिखाया गया है। यह लगभग उतार-चढ़ाव वाली प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। 1981 में जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान और स्विट्जरलैंड भारत में शीर्ष निवेश करने वाले देश थे। इन देशों का कुल एफडीआई प्रवाह का 86 प्रतिशत हिस्सा था। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि जर्मनी को छोड़कर लगभग सभी देशों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में सकारात्मक रुझान है। 1990 में, शीर्ष पांच निवेश करने वाले देश यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूके और इटली थे और साथ में उनका लगभग 57 प्रतिशत एफडीआई प्रवाह था।

तालिका 3: 1981 से 1990 तक भारत में देश-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रुझान (अमेरिकी डॉलर मिलियन)								
वर्ष	अमेरिका	जर्मनी	जापान	यूके	इटली	स्विट्जरलैंड	अन्य	कुल
1981	2.6	6.2	0.7	0.8	0.1	0.5	1.6	12.5
1982	5.3	3.7	26.5	1.7	2	1.2	23.6	66.2
1983	13.7	4.8	15.9	9.7	1.1	1.1	14.7	61
1984	7.9	2.5	5.4	1.6	0.7	0.4	80.9	99.4
1985	32.3	9.6	12.7	3.0	5.6	0.7	38.1	102
1986	23.3	16.0	6	6.1	1.9	2.6	30.4	84.9
1987	22.8	7.6	5.3	6.5	2.3	6.8	31.8	83.1
1988	69.8	22.3	12.5	10.0	22.0	1.2	35	172.3
1989	38.3	72	5.4	20.6	3	4.8	47.6	195.2
1990	19.7	5.4	2.9	5.2	3.9	7.7	28.5	73.3

स्रोत: जी अख्तर, आईजेएसएस (2013)



- उदारीकरण पूर्व चरण के दौरान क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह की प्रवृत्तियां

भारत में क्षेत्रवार एफडीआई अंतर्वाह तालिका 4 और 5 में दिखाया गया है। उदारीकरण से पहले के चरण में, अधिकांश एफडीआई स्टॉक प्राकृतिक संसाधन चाहने वाले और व्यापारिक प्रकार के लिए था। यह कच्चे माल पर केंद्रित था। 1948 के मध्य में, एफडीआई का उच्चतम हिस्सा चाय बागानों और जूट में था (तालिका 4)। एफडीआई नीति से यह स्पष्ट है कि स्थानीय लाभ बाजार चाहने वाले एफडीआई को बढ़ावा देते हैं। बाद में, पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 1950 और 1960 के दशक में भारत में अपनी रुचि दिखाई।

तालिका 4: 1948 से 1980 तक भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रुझान (करोड़ रुपये में)						
वर्ष	वृक्षारोपण	खुदाई	पेट्रोलियम	उत्पादन	सेवाएं	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह
Mid 1948	64	35.84	23.04	51.2	81.92	256.0
March 1964	105.9	4.7	143.3	229.3	82.3	565.5
March 1974	107.2	6.4	137.9	628.6	39.8	916.0
March 1980	38.5	7.8	36.8	811.6	38.5	933.2

स्रोत: कुमार, 1995

उपरोक्त तालिका 4 से स्पष्ट है कि 1964 के बाद से विनिर्माण क्षेत्र ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। इसका कारण गैर-विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई स्टॉक के परिसमापन के कारण हो सकता है जो 1971 में सामान्य बीमा कंपनियों जैसी सरकारी गतिविधियों में ले रहा था। 1980 में व्यापार,





उद्योग और विदेशी सहयोग नीतियों के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को और अधिक आकर्षित करने में मदद की। एफडीआई अंतर्वाह (आरबीआई, 1985)। निम्न तालिका 5 1981 से 1990 तक भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के रुझानों को दर्शाती है।

तालिका 5: 1981 से 1990 तक भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रुझान

(अमेरिकी डॉलर मिलियन)

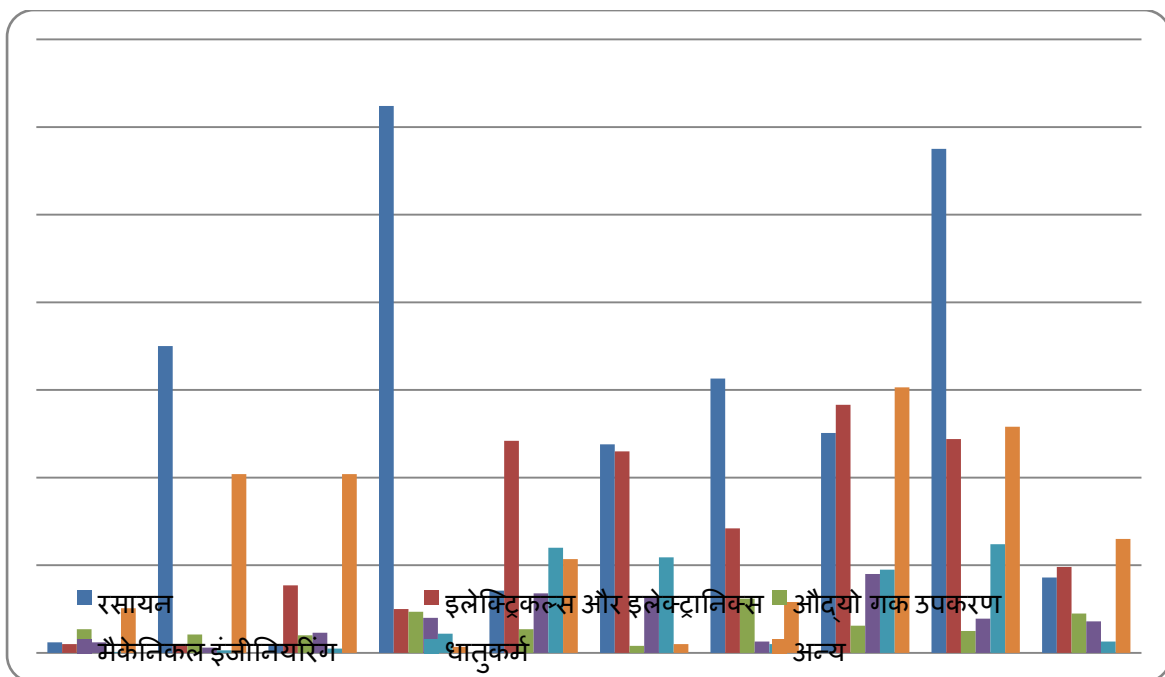
वर्ष/ क्षेत्र	रसायन	इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स	औद्योगिक उपकरण	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	धातुकर्म	अन्य	कुल	शीर्ष क्षेत्रों का%	5
1981	1.2	1.0	2.7	1.2	0.1	5.1	11.3	54.87	
1982	35.0	1.0	2.1	0.6	0.3	20.4	59.4	65.66	
1983	0.8	7.7	2.0	2.3	0.5	20.4	33.7	39.47	
1984	62.4	5.0	4.7	4.0	2.2	0.7	79.0	99.11	
1985	7.1	22	2.7	6.8	12.0	10.7	68.7	83.2	
1986	23.8	23.0	0.8	6.4	10.9	1.0	65.9	98.48	
1987	31.3	12	6.2	1.3	1.0	5.8	59.8	90.3	
1988	25.1	28.3	3.1	9.0	9.5	30.3	105.0	71.23	
1989	57.5	24	2.5	3.9	12.4	25.8	126.0	79.6	
1990	8.6	9.8	5	3.6	1.3	13.0	40.8	68.14	

स्रोत: जी अख्तर, आईजेएसएसआई (2013)

उपरोक्त तालिका 5 से पता चलता है कि 1981 में, शीर्ष पांच क्षेत्र जिन्होंने एफडीआई को आकर्षित किया है, वे औद्योगिक मशीनरी, रसायन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और धातु विज्ञान थे, इन क्षेत्रों में एफडीआई प्रवाह का 54.87 प्रतिशत हिस्सा था। 1990 में, शीर्ष पांच क्षेत्र

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, औद्योगिक मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और धातु विज्ञान थे, ये कुल एफडीआई प्रवाह का **68.14** प्रतिशत हिस्सा थे।

भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्पष्ट प्रवृत्ति को चित्र 2में दर्शाया गया है। यह उन सभी क्षेत्रों में एफडीआई प्रवाह में उच्च उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जिनमें से रासायनिक क्षेत्र में उच्च स्तर का उतार-चढ़ाव देखा गया है।



चित्र 2: 1981 से 1990 तक भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रुझान

स्रोत: जी अख्तर, आईजेएसएसआई (2013)

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उदारीकरण -पूर्व चरण के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में पूर्ण वृद्धि हुई थी। भारत सरकार ने एफडीआई के प्रति एक प्रतिबंधित नीति और घरेलू निवेशकों के प्रति एक संरक्षणवादी नीति अपनाई। लेकिन 1980 के दशक में सरकार ने अपनी नीति को उदार बनाना शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप भारत में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय वितरण स्पष्ट करता है कि विदेशी निवेशकों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को अधिक आकर्षण मिला। यह सरकार की आयात प्रतिस्थापन नीति



के कारण हो सकता है। 1981 में, भारत जर्मनी से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त कर रहा था , लेकिन 1990 में, अमेरीका भारत में एफडीआई प्रवाह का सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। क्षेत्र -वार विश्लेषण से पता चलता है कि 1981 में, औद्योगिक मशीनरी सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त कर रही थी , जबकि 1990 में, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उच्चतम एफडीआई प्राप्त कर रहे थे। हालांकि , 1991 से पहले, एफडीआई प्रवाह की समग्र तस्वीर विनिर्माण क्षेत्र को छोड़कर उत्साहजनक नहीं थी।

### निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन में 1991-92 से 2020-21 तक 26 वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण करके भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रदर्शन की जांच करने का प्रयास किया गया है। योगदान की जांच करने के लिए , विदेशी इक्विटी प्रवाह का उपयोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है , जबकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का उपयोग आर्थिक विकास के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है।

### संदर्भ

1. राव और सिंह (2017): - अधिक प्रभावी शासन की ओर, मैकमिलन, दिल्ली, 2003।
2. प्रदीप बैज (2017): - "निजीकरण: आर्थिक सुधार के लिए मजबूरियां और विकल्प " आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, अक्टूबर 12, 2002, पीपी। 4189-4195।
3. मुखर्जी, टी.के. और नाका , अत्सुयुकी, एन. (1995), "मैक्रोइकॉनॉमिक वेरिएबल्स और जापानी स्टॉक मार्केट के बीच गतिशील संबंध : एक वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल का एक अनुप्रयोग", द जर्नल ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च, वॉल्यूम। 28, नंबर 2, पीपी. 223-237.
4. नेल्सन, सी.आर., और प्लॉसर , सी.आई. ( 1982), "ट्रेंड्स एंड रैंडम वॉक इन मैक्रोइकॉनॉमिक टाइम सीरीज़ सम एविडेंस एंड इंप्लीकेशंस ", जर्नल ऑफ़ मॉनेटरी



इकोनॉमिक्स 10(1982), पीपी- 139-162, नॉर्थ-हॉलैंड पब्लिशिंग कंपनी।

5. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (1999), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ओईसीडी बेंचमार्क परिभाषा, तीसरा संस्करण, पेरिस।
6. पॉल, एल.सी., सुमन, ए.ए., सुल्तान, एन. (2013), "मैथडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (पीसीए) मेथड", आईजेसीईएम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्प्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट , वॉल्यूम। 16 अंक 2, मार्च 2013, आईएसएसएन (ऑनलाइन): 2230-7893 [www.IJCEM.org](http://www.IJCEM.org)
7. फिलिप्स, पी. एंड पेरोन (1988), "टेस्टिंग फॉर ए यूनिट रूट इन टाइम्स सीरीज़ रिग्रेशन ", बायोमेट्रिका, 75, पीपी। 335-346।
8. रतनपाकोर्न, ओ. और शर्मा , एस.सी. ( 2007), "अमेरिकी स्टॉक रिटर्न्स और मैक्रोइकॉनॉमिक वेरिएबल्स के बीच गतिशील विश्लेषण ", एप्लाइड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, 2007, 17, पीपी। 369-377।
9. रोमर, पी.एम. ( 1990), "एंडोजेनस टेक्नोलॉजिकल चेंज ", जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 98 (5), अक्टूबर (भाग 2), S71-S102।
10. सीतापति, के. (2006), "उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई मुद्दे ", आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी प्रेस,